नवभारत टाइम्स

राजधानी में 11 लाख पाठक

माघ 16 शक 1914 ❏ माघ शुक्ल 13 विक्रम 2049 ❏ **नयी दिल्ली** ❏ शुक्रवार 5 फरवरी 1993 ❏ वर्ष 47 संख्या 36 ❏ रु. 1.50 ❏ पृष्ठ 14

रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के मुद्दे पर मतभेद

नयी दिल्ली, 4 फरवरी (एजेंसी)। रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के मुद्दे पर देश के उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों में मतभेद हैं। एक ओर उद्योगपतियों का तर्क है कि पूर्ण परिवर्तनीयता जल्द से जल्द लागू होनी चाहिए तो दूसरी ओर अर्थशास्त्रियों की राय है कि यह वक्त इस तरह का कदम उठाने का नहीं है।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ने अपने एक बजट पूर्व सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला है।

भारतीय उद्योग व वाणिज्य महासंघ (फिक्की) के अध्यक्ष कांतिकुमार पोद्दार और एसोचैम अध्यक्ष एन.एम. धुलधोया सहित अनेक उद्योग प्रतिनिधियों ने पूर्ण परिवर्तनीयता की वकालत की है। श्री पोद्दार ने तर्क दिया कि 60:40 अनुपात की मौजूदा आंशिक परिवर्तनीयता के तहत निर्यातकों को एक अप्रत्यक्ष कर चुकाना पड़ रहा है। जबकि सरकारी लेन देन को इससे अप्रत्यक्ष सब्सिडी मिल रही है। श्री धुलधोया ने कहा कि पूर्ण परिवर्तनीयता से निर्यातकों की शत प्रतिशत आय को विदेशी मुद्रा के बाजार भाव पर बेचना संभव होगा, लिहाजा विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में सुधार होगा।

अलबत्ता, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष डा. मैल्कम एस. आदिसेशिया के मुताबिक परिवर्तनीयता अंश बढ़ाने या पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए आगामी बजट का समय अनुकूल नहीं है। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डा. एस. एल. राव की राय है कि पूर्ण परिवर्तनीयता लाने से पहले मुद्रास्फीति घटने का इंतजार करना चाहिये। साथ-साथ विदेशी निवेश और निर्यात के स्तर में भी अपेक्षित सुधार होना जरूरी है। उनका कहना है कि तथाकथित अनिवार्य आयात वस्तुओं के दाम अभी भी सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। उनकी राय इन वस्तुओं के दाम पूर्ण परिवर्तनीयता आने के बाद बेतहाशा बढ़ जायेंगे, इसलिए पहले उनके दाम घटने की प्रतीक्षा होनी चाहिए।

अलबत्ता, उन्होंने कहा कि भारत चीन की तरह परिवर्तनीय अंश को मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर सकता है, बशर्ते अनिवार्य आयात का खर्चा बाजार भाव पर बिकने वाले अंश से पूरा किया जाये।

कर्नाटक सरकार के आर्थिक सलाहकार डा. जी. थिमिया के मुताबिक पूर्ण परिवर्तनीयता की पहली शर्त यह है कि मुद्रास्फीति कम की जाये। देश में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, हालांकि थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आयी है।

उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग अभी भी लागत कम नहीं कर पाये हैं। इसके अलावा हमारा ब्याज दर ढांचा भी इतना आकर्षक नहीं हो पाया है कि समुचित विदेशी निवेश आकृष्ट हो सके। साथ ही परिवर्तनीयता के बाद उठने वाले आयात के तूफान को बांधने के लिए निर्यात बढ़ने की संभावना भी नहीं दिख रही। इसलिए इस वक्त परिवर्तनीयता के अंश को बढ़ाने में नुकसान है। इसे कम से कम एक साल तक मुल्तवी करना चाहिये।

उधर, राष्ट्रीय वित्त संस्थान के प्रो. जे.डी. अग्रवाल ने कहा है कि सरकारी विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति देखते हुए पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करने में कोई हर्ज नहीं है। और कुछ नहीं तो परिवर्तनीय अंश को बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जा सकता है। अर्थशास्त्री से उद्योगपति बने श्री डी.एन. पटौदिया ने भी पूर्ण परिवर्तनीयता का समर्थन किया है।